में है।

(ख) इस परियोजना के लाभ और लागत को दोनों राज्यों के बीच बराबर बांटने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश ने 133 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है जबकि मध्य प्रदेश ने 87 करोड़ रुपये का अंशदान किया है।

(ग) राजघाट बांध परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 46 करोड़ रुपये की वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान 23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की है जिसमें से 11.5 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

गंगऊ पर भंडारण बांध

2621. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **:**

(क) क्या केन नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक संयुक्त नदी है, और मध्य प्रदेश द्वारा इस नदी के साथ गंगऊ स्थान पर एक भंडारण बांध का निर्माण करने की एक संयुक्त परियोजना प्रस्तावित है और क्या अनुमानित जल की उपलब्धता और उसके वितरण के संबंध में दोनों राज्यों के बीच सहमति न हो पाने के कारण इस परियोजना को अंतिम रूप नही दिया जा सका;

(ख) क्या केन बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बांध में भंडारित जल बांदा जिले के क्षेत्रों के लिए सिंचाई साधन के रूप में लाभकारी होगा; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) गंगऊ परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के बाद इस परियोजना की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है।

Pending Water Disputes

2622. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 448 given in the ajya Sabha on 25th February, 1999 and state:

(a) whether Government have adopted any new strategy to settle the pending disputes among States on the Inter-State Water disputes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOM PAL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Reliability and efficiency of cyclone forecasting

2623. SHRI LAJPAT RAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the machinery for flood and cyclone forecasting is working efficiently and reliably;

(b) if so, the track record of flood and cyclone forecasting in our country; and

(c) the steps taken/being taken to improve the efficiency and reliability in flood forecasting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The record of flood forecasting activities of Central Water Commission and that of cyclone forecasting of India Meteorological Department have been satisfactory and have been appreciated for the reliability and timely forecasts, particularly of major flood and cyclone events. The performance in terms of accuracy of flood forecasts ranges between 94% to 98% in the last ten years. India's cyclone forecasting capability is such that no cyclone approaching Indian Coast from any part of the Indian Ocean can escape detection.

(c) To improve the efficiency and reliability of flood forecasts, the techniques are being constantly reviewed, updated and modernised. The communication system is constantly modernised by introducing satellite technology to advance the warning time and quicken the data transmission.

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रुपेन नदी और बाण सागर परियोजना संबंधी समझौता

2624. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी के जल के बंटवारे और बाण सागर परियोजना के संबंध में वर्ष 1973 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा अपने भाग के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए परियोजना निर्माणाधीन है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा तीनों के बीच जल के बटवारे और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है और तीनों राज्यों के किस स्तर के व्यक्ति इस समिति के सदस्य है और उनके नाम क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यंत कठिनाई का सामना किया जा रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश द्वारा नियोजित 3 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं सिंचाई के वास्ते जल के उनके स्वयं के हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) बेसिन राज्यों के बीच सोन जल के बंटवारे के लिए परस्पर स्वीकार्य प्रस्तावों को तैयार करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई थी। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष थे । तीन राज्यों के प्रमुख इंजीनियर इस समिति के सदस्य थे। अंतर राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण बेसिन की कुछ परियोजनाएं स्वीकृत नही की जा सकी।

Ground water availability in the country

2625. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Govemment have made any estimate on the ground water availability in the country;

(b) if so, the State-wise and region-wise details thereof;

(c) whether any effort is being made at the national level for the optimum utilisation of the available water resources in the country;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken particularly to utilise the monsoon runoff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) State-wise availability of replenish able ground water resources is given in the enclosed statement. *(See* below)

(c) to (e) The Union Government has taken various policy and programme initiatives for the optimum utilisation of available water resources in the country. These include adoption of National Water Policy (1987), Command Area Development Programme, preparation of National Perspective Plan for transfer of water from surplus basins to water deficit areas, water management practices promoting efficient and economic use of water for various purposes, emphasis on water conservation through various methods in cluding use of latest technologies and people's participation in management of water for diverse use, setting up of National Commission for Integrated Water Resources Development Plan in September, 1996 as well as launching of Accelerated Irrigation Benefits Programme since 1996-97 for expeditious completion of selected ongoing major and medium irrigation and multipurpose projects. Government is also promoting rain water harvesting and watershed management to replenish ground water.

Statement

Stale-wise availability of replenishable ground water resources.

SI.No.	States/UTs	Total Ground Water Resources (mham/Yr)
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	3.52916
2.	Arunachal Pradesh	0.14385
3.	Assam	2.47192
4.	Bihar	3.35213
5.	Goa	0.02182
6.	Gujarat	2.03767
7.	Haryana	0.85276
08.	Himachal Pradesh	0.03660